

Daily Current Affairs

Date : 22 July, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	पीएम कुसुम योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर
2.	राजस्थान में ओरण भूमि
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स (राजस्थान) 1. कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क 2. सरिस्का अभ्यारण्य में पहली बार तितलियों का सर्वेक्षण
4.	भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र
5.	मंडोवी नदी पर 'रो-रो' फेरी सेवा की शुरुआत
6.	SBI: विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक
7.	श्री गॉर्जेस डैम
8.	AK-203 राइफल
9.	क्रोनिक वेनस इन्सफिशिएंसी रोग
10.	पश्चिमी घाट में नई लाइकेन प्रजाति: एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका
11.	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस
12.	वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार

राजस्थान परिदृश्य

पीएम कुसुम योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर

➔ चर्चा में क्यों?

- राजस्थान 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (PM कुसुम योजना) के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का अग्रणी राज्य है।



➔ मुख्य बिंदु :

- PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान में अब तक कुल 1,305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 1,190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट विगत एक वर्ष के भीतर विकसित किए गए हैं।
- राजस्थान कम्पोनेंट-ए में देश में अग्रणी राज्य है। कम्पोनेंट-ए में 457 मेगावाट के प्लांट अकेले राजस्थान में हैं। वहीं कम्पोनेंट-सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

- इस योजना से प्रदेश के 1,70,000 से अधिक किसानों को खेती के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है।
- इस योजना में प्रदेश में 12 हजार मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का लक्ष्य है।

❖ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

पीएम कुसुम:

- ♦ **शुरुआत :** मार्च, 2019
- ♦ **नोडल मंत्रालय :** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- ♦ **उद्देश्य :** किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करना।

योजना के तीन घटक (Components):

1. कम्पोनेन्ट-ए:

- ♦ 500 किलोवाट (kW) से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले व्यक्तिगत संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना करना।
- ♦ ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत और नुकसान से बचने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को अधिसूचित सब-स्टेशनों के पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थापित करना।
- ♦ उत्पादित विद्युत की खरीद स्थानीय डिस्कॉम (Distribution Company) द्वारा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा निर्धारित पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर की जाती है।
- ♦ **नोट :** राजस्थान में कंपोनेन्ट-ए का कार्यान्वयन प्रारंभ में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) द्वारा किया जा रहा था, जिसे 23 जुलाई, 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दिया गया।

2. कम्पोनेन्ट-बी:

- ♦ 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना।
- ♦ इस घटक के तहत 3 से 10 हॉर्सपावर (HP) तक के स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7.5 हॉर्सपावर तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देय है।
- ♦ जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर हैं, वे इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के पात्र हैं।
- ♦ इस योजना के अन्तर्गत किसानों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। शेष 60 प्रतिशत भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बराबर-बराबर 30-30 प्रतिशत दिया जाता है।
- ♦ 40 प्रतिशत में से किसान बैंक से 30 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है और शेष 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा।
- ♦ योजना के कम्पोनेन्ट-बी का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

3. कम्पोनेन्ट-सी (फीडर लेवल सोलराईजेशन)

- ♦ नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 4 दिसम्बर, 2020 को पीएम-कुसुम योजना के घटक सी के तहत फीडर लेवल सोलराईजेशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसमें ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता जो एक या एक से अधिक अलग-अलग कृषि फीडरों की वार्षिक बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैपेक्स मोड या रेस्को मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है।
- ♦ मंत्रालय ने 4,00,000 पम्प सेटों का सोलराईजेशन करने का लक्ष्य स्वीकृत किया है।

राजस्थान में ओरण भूमि

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से गठित जितेंद्र राय गोयल समिति ने ओरण भूमि को संरक्षित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों से ओरण, मालवन, देवराई, रखबनी, देवघाट, मंदिर वन, देव वन और बाग आदि के नाम वाली भूमि का ब्यौरा माँगा है।

➔ मुख्य बिंदु :

- सदियों पूर्व ग्रामीणों ने माजीसा, जांबोजी, जोगमाया, भोमियाजी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेवजी, मामाजी आदि लोक देवी-देवताओं के नाम पर ओरण की भूमि को संरक्षण प्रदान किया था।
- इन ओरणों को सांस्कृतिक आस्था और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन समय के साथ इन पवित्र स्थलों पर अतिक्रमण की घटनाएँ बढ़ी हैं; जैसे - अवैध खनन, अवैध निर्माण और अतिक्रमण।
- इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जहाँ से ओरण की जमीनों को संरक्षित रखने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।

Daily Current Affairs

Date : 22 July, 2025



राजस्थान में ओरण भूमि की स्थिति (वर्ष 2024 में सम्पन्न ओरण भूमि सर्वे के अनुसार) :

क्रम	जिला	ओरण भूमि (हेक्टेयर में)
1	जैसलमेर	2,02,130
2	बाड़मेर	83,000
3	फलोदी	31,000
4	बालोतरा	18,301
5	बीकानेर	13,000

❖ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

जितेंद्र राय गोयल समिति:

- ♦ सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने राजस्थान के देवबन ओरण के संरक्षण हेतु 'जितेंद्र राय गोयल' की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की।
- ♦ देवबन ओरण के संरक्षण हेतु याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन मसीह की पीठ द्वारा की गई।

न्यूज़ इन शॉर्ट्स (राजस्थान)

क्र. सं.	न्यूज़
1.	कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क  ♦ 7.42 करोड़ की लागत से कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क बनाया गया है। ♦ इस पार्क में 29 प्रजातियों के भारतीय व विदेशी सांप जैसे - इंडियन कोबरा, रसल्स वाइपर, इंडियन पॉयथन, बॉल पॉयथन और मिल्क स्नेक आदि को संरक्षित किया जाएगा, जिससे पर्यटक सांपों की विविध दुनिया को करीब से देख सकेंगे।
2.	सरिस्का अभ्यारण्य में पहली बार तितलियों का सर्वेक्षण 

- ◆ 19 व 20 जुलाई, 2025 को अलवर स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवन व पारिस्थितिक तंत्र की व्यापक समझ विकसित करने के उद्देश्य से पहली बार तितलियों की गणना की गई।
- ◆ यह डाटा आगामी वर्षों में जैव विविधता के संरक्षण का आधार बनेगा और शोधकर्ताओं के शोध कार्य में उपयोगी साबित होगा।

पर्यावरण में तितलियों की भूमिका :

- ◆ **परागण (Pollination):** तितलियाँ फूलों से अमृत (NECTAR) चूसते समय पराग एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं, जिससे पौधों का प्रजनन संभव होता है।
- ◆ **जैव विविधता का संकेतक (Bio-indicator):** तितलियाँ पर्यावरण की गुणवत्ता और जैव विविधता का संकेत देती हैं, जहाँ तितलियाँ अधिक होती हैं, वह क्षेत्र अधिक स्वस्थ और जैविक रूप से समृद्ध होता है।

CIVIL
SERVICES

राष्ट्रीय परिदृश्य

भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से त्याग-पत्र दिया।



➔ मुख्य बिंदु :

- ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अपने पद से त्याग-पत्र दिया है। इनसे पूर्व वी.वी. गिरि (जुलाई, 1969) और आर. वेंकटरमण (जुलाई, 1987) अपने पद से त्याग-पत्र दे दिये थे।
- ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।
- ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से त्याग-पत्र दिया।

भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद:

- **अनुच्छेद- 63:** भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा।
- **अनुच्छेद- 64:** उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
- **अनुच्छेद- 65:** आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा।
- **अनुच्छेद- 66:** उपराष्ट्रपति का निर्वाचन:
 - संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से निर्वाचन होगा।
 - उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, और चुने जाने पर वह पद त्याग देगा।
 - **पात्रता:**
 - भारत का नागरिक हो।
 - 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
 - राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो।
- **अनुच्छेद- 67:** पदावधि
 - उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
 - वह राष्ट्रपति को लिखित पत्र द्वारा त्याग-पत्र दे सकता है।
 - राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव से हटाया जा सकता है (14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक)।
 - कार्यकाल पूरा होने पर भी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक वह पद पर बना रह सकता है।

- **अनुच्छेद- 68:** रिक्ति की स्थिति में चुनाव
 - उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, पद की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जाएगा।
 - आकस्मिक रिक्ति होने पर शीघ्र चुनाव कराया जाएगा और नया उपराष्ट्रपति 5 वर्षों का पूरा कार्यकाल पाएगा।
- **अनुच्छेद- 69:** शपथ / प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष शपथ लेगा।
- **अनुच्छेद- 70:** अन्य आकस्मिकताएँ, संसद किसी अन्य आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की व्यवस्था कर सकती है।
- **अनुच्छेद- 71:** निर्वाचन संबंधी विवाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी सभी शंकाओं का निवारण केवल उच्चतम न्यायालय करेगा।

मंडोवी नदी पर 'रो-रो' फेरी सेवा की शुरुआत

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर देश की पहली Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) फेरी सेवा शुरू की हैं।



➔ मुख्य बिंदु :

- यह सेवा चोराओ द्वीप और रिबंदर के बीच तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन सुनिश्चित करती है।
- इस परियोजना के अंतर्गत दो आधुनिक फेरी - 'गंगोत्री' और 'द्वारका' चलाई जाएंगी।

RoRo (Roll-on/Roll-off):

- RoRo (Roll-on/Roll-off) एक ऐसी जल परिवहन प्रणाली है, जिसमें यात्री अपने वाहनों के साथ फेरी पर सवार हो सकते हैं।
- यात्रियों को गाड़ी से उतरने की आवश्यकता नहीं होती।
- यह प्रणाली उन क्षेत्रों में बेहद उपयोगी है जहाँ सड़क नेटवर्क सीमित हो।



SBI: विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया।



➔ मुख्य बिंदु :

- ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, 18 अक्टूबर, 2025 को वाशिंगटन डीसी में IMF/विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक' नामक वार्षिक कार्यक्रम में SBI के अध्यक्ष सीएस शेटी को यह पुरस्कार प्रदान करेगी।
- यह सम्मान ग्राहक सेवा पर SBI के असाधारण ध्यान और डिजिटल परिवर्तन में इसकी प्रभावशाली प्रगति हेतु प्रदान किया जायेगा।

Daily Current Affairs

Date : 22 July, 2025



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) :

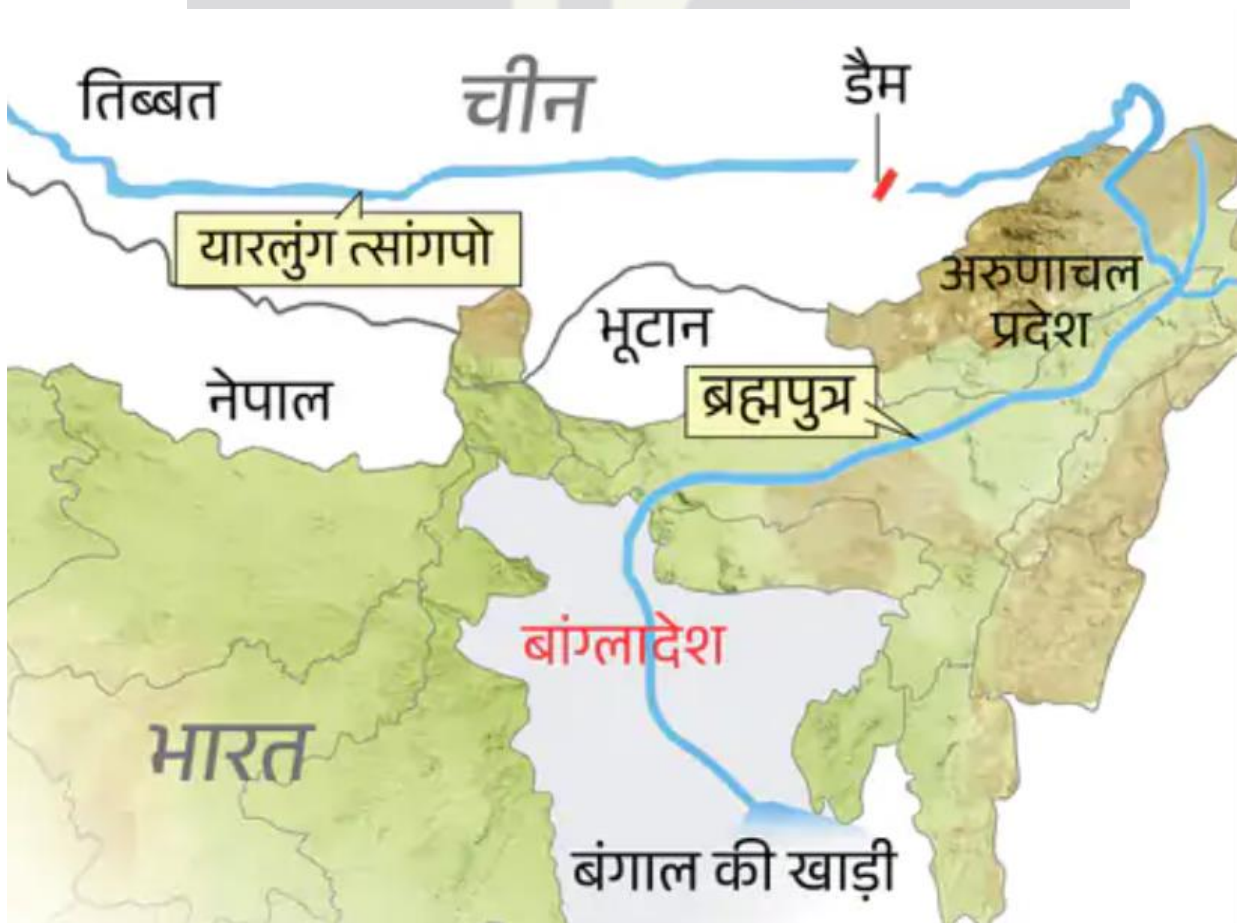
- यह एक वैधानिक संस्था है।
- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 43वाँ सबसे बड़ा बैंक है।
- **मुख्यालय :** मुंबई।
- **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नवाचार :** हर घर लखपति योजना और SBI पैट्रन्स योजना, योनो (यू ओनली नीड वन) एप, SBI एनीव्हेयर, SBI इनटच, SBI पे, SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप, SBI ग्राम सेवा, SBI ग्रीन मैराथन, SBI बाल कल्याण कोष इत्यादि।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

श्री गॉर्जेस डैम

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी (चीन में यारलुंग सांगपो) पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर डैम बनाना शुरू किया।



➔ मुख्य बिंदु :

- AFP की रिपोर्ट के अनुसार, इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर, 2024 में मंजूरी प्रदान की गई थी। यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे न्यिंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर (लगभग 12 लाख करोड़ रुपए) बताई गई है।

- इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया था।
- यह बांध हिमालय में एक विशाल गॉर्ज के दूसरी तरफ बनाया जा रहा है, जहां नदी भारत की सीमा (अरुणाचल प्रदेश) के पास यू-टर्न लेती है।
- चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक परियोजना में पांच सीढ़ीदार (कैस्केड) हाइड्रोपावर स्टेशन शामिल होंगे।
- यह डैम साल भर में 300 अरब यूनिट (kWh) से अधिक बिजली बनाएगा। इस बिजली से 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली तंत्र :



Daily Current Affairs

Date : 22 July, 2025



- **उद्गम** : दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बती पठार के दक्षिण-पश्चिमी भाग में 5,300 मीटर की ऊँचाई पर, कोंग्यू त्सो झील के पास स्थित है।
- **लंबाई** : 2,900 किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ, ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है।
- ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले चार देशों - तिब्बत (चीन), भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर 2,900 किलोमीटर की दूरी तय करती है।

उपनाम :

- **तिब्बत** - त्सांगपो।
- **चीन** - यारलुंग जांगबो।
- **असम घाटी** - दिहांग या सियांग, सादिया के दक्षिण में : ब्रह्मपुत्र।
- **बांग्लादेश** - जमुना नदी और अंततः गंगा के साथ मिलकर विशाल सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है।
- **माजुली और उमनंदा** : विश्व का सबसे बड़ा (माजुली) और सबसे छोटा (उमनंदा) नदी द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित हैं।

प्रमुख सहायक नदियाँ :

बाईं ओर की सहायक नदियाँ	दाईं ओर की सहायक नदियाँ
ल्हासा नदी	कामेंग नदी
न्यांग नदी	मानस नदी
परलुंग जांगबो नदी	बेकी नदी
धनश्री नदी	राइदक नदी
	जलढाका नदी
कोलोंग नदी	तीस्ता नदी
लोहित नदी	सुबनसिरी नदी

Daily Current Affairs

Date : 22 July, 2025



- **भारत में प्रवाह :** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
- **ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर :** डिब्रूगढ़, पासीघाट, नीमती, तेजपुर और गुवाहाटी।
- **जलविद्युत परियोजनाएँ :** सुबनसिरी, अपर लोहित, कामेंग (अरुणाचल प्रदेश), रंगीत जलविद्युत परियोजना, तीस्ता जलविद्युत परियोजना (सिक्किम), कोपिली जलविद्युत परियोजना (असम), न्यू उमटू जलविद्युत परियोजना (मेघालय), दोयांग जलविद्युत परियोजना (नागालैंड), लोकटक जलविद्युत परियोजना, तिपाइमुख जलविद्युत परियोजना (मणिपुर), तुइबाई जलविद्युत परियोजना, तुइरियल जलविद्युत परियोजना और ढलेस्वरी जलविद्युत परियोजना (मिज़ोरम)।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

AK-203 राइफल

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, अमेठी में बनी पहली AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई।



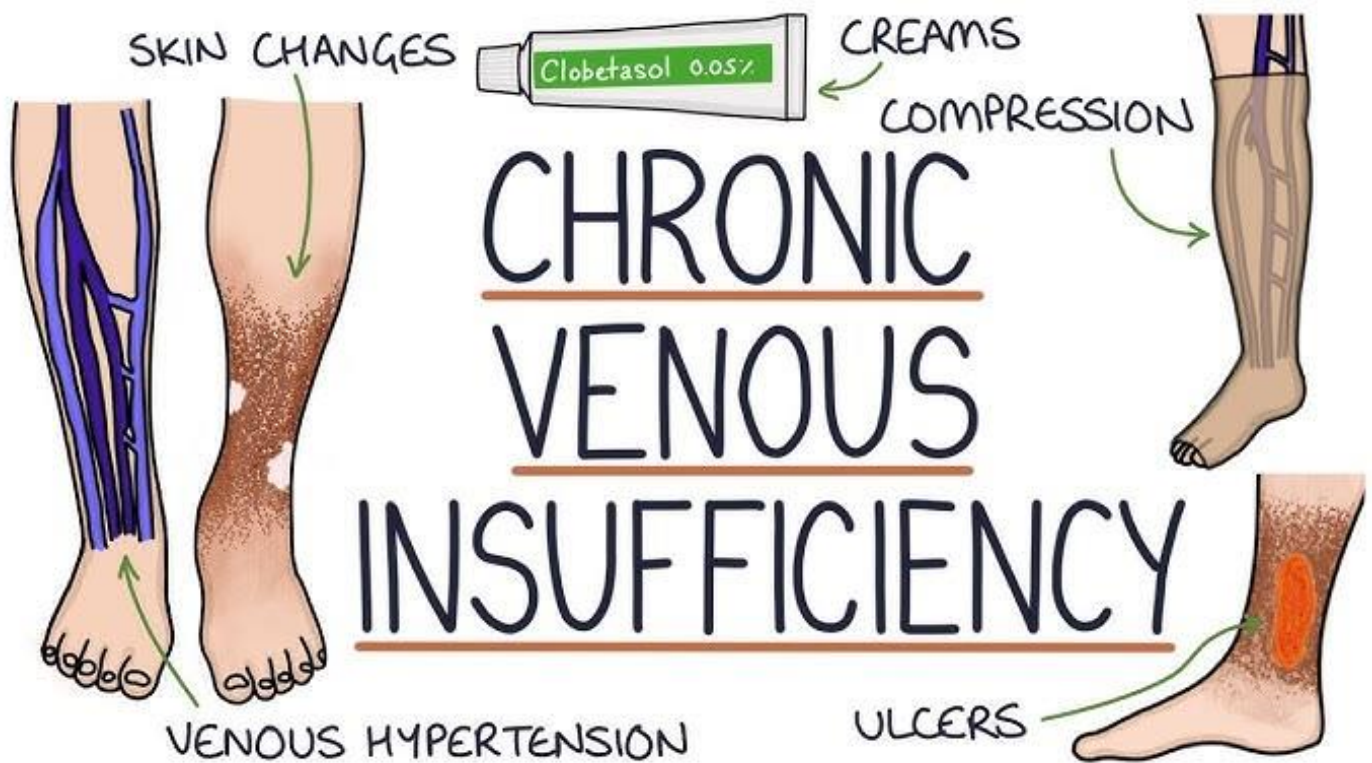
➔ मुख्य बिंदु :

- भारत-रूस की संयुक्त कंपनी इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) ने AK-203 राइफलों का निर्माण किया है।
- AK-203, प्रसिद्ध कलाशिकोव राइफल श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है।
- इसे भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- यह राइफल LoC (नियंत्रण रेखा) और LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोग की जाती है।

क्रोनिक वेनस इन्सफिशिएंसी रोग

➔ चर्चा में क्यों?

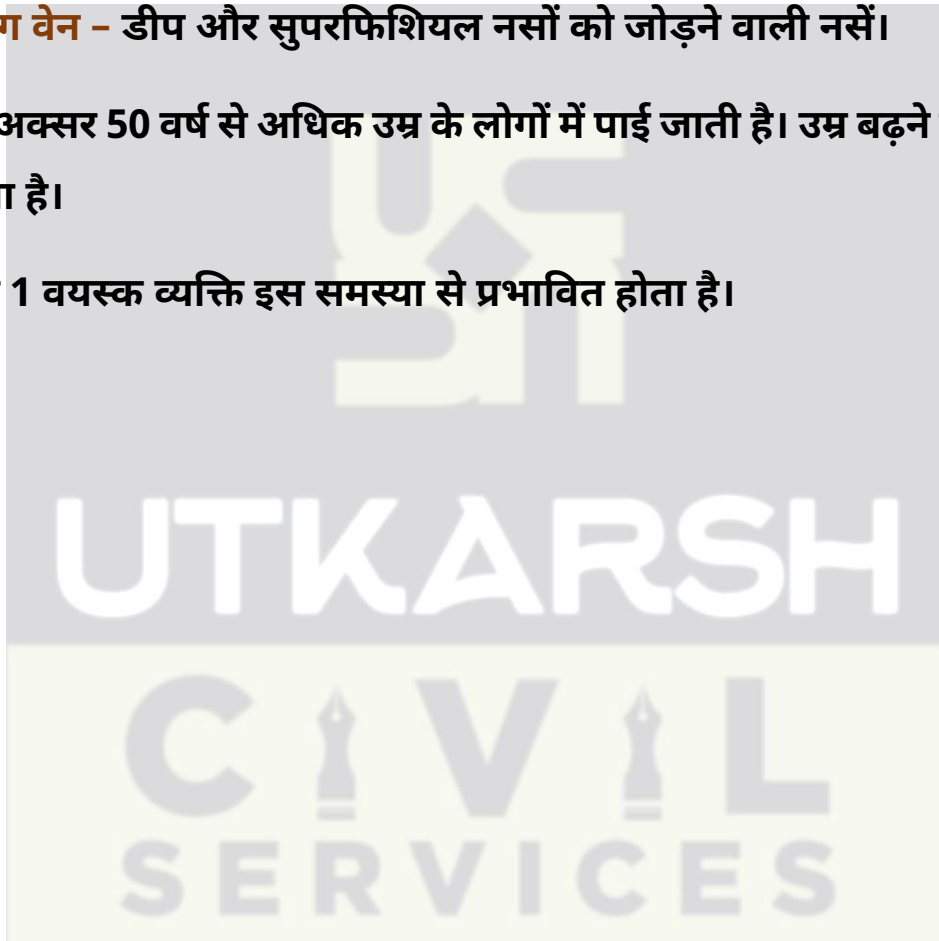
- हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प में क्रोनिक वेनस इन्सफिशिएंसी (Chronic Venous Insufficiency: CVI) नामक बीमारी का पता चला है।



➔ मुख्य बिंदु :

- CVI एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पैरों की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
- इससे रक्त का प्रवाह हृदय की ओर सुचारु रूप से नहीं हो पाता।
- नसों में मौजूद वाल्व रक्त को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करते हैं।
- जब ये वाल्व खराब हो जाते हैं, तो रक्त नीचे की ओर जमा होने लगता है।
- जमा हुआ रक्त नसों में अधिक दबाव उत्पन्न करता है।

- यह समस्या शरीर की तीन प्रकार की नसों को प्रभावित कर सकती है:
 - **डीप वेन** - मांसपेशियों के अंदर गहरी एवं बड़ी नसें।
 - **सुपरफिशियल वेन** - त्वचा के नजदीक की नसें।
 - **पफॉरेटिंग वेन** - डीप और सुपरफिशियल नसों को जोड़ने वाली नसें।
- यह स्थिति अक्सर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती है। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता है।
- हर 20 में से 1 वयस्क व्यक्ति इस समस्या से प्रभावित होता है।



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

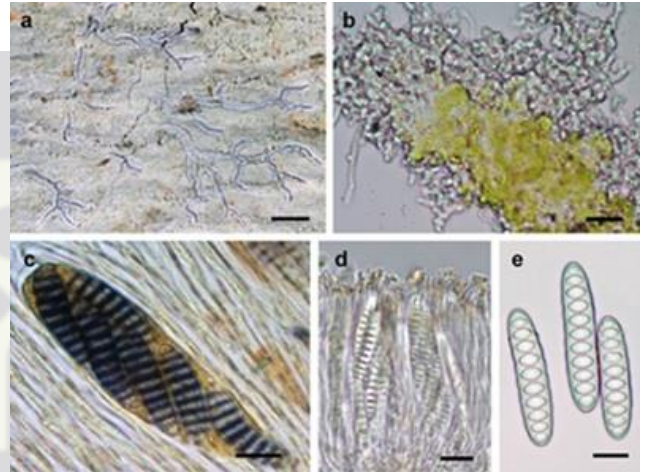
पश्चिमी घाट में नई लाइकेन प्रजाति: एलोग्राफा इप्प्यूसोरेडिका

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत के पश्चिमी घाट में 'एलोग्राफा इप्प्यूसोरेडिका' नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की खोज की गई।

➔ मुख्य बिंदु :

- यह खोज MACS-अधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है।
- यह खोज सहजीवी विकास की एक नई परत को सामने लाती है।
- लाइकेन, कवक और प्रकाश संश्लेषक सजीवों (जैसे- हरे शैवाल या सायनोबैक्टीरिया) के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण हैं।
- लाइकेन मृदा निर्माण में सहायक होते हैं।
- ये वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।
- जैव श्रृंखलाओं की स्थिरता बनाए रखने में इनका योगदान होता है।
- खोज का केंद्र पश्चिमी घाट है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है।



महत्त्वपूर्ण दिवस

राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस

➔ चर्चा में क्यों?

- प्रति वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है।



➔ मुख्य बिंदु :

- इसी दिन वर्ष 1947 में संविधान सभा ने तिरंगा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया।

- भारतीय तिरंगा 3:2 अनुपात में बना आयताकार ध्वज होता है, जिसमें तीन क्षैतिज रंगों के मध्य 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होता है, जो न्याय और धर्म का प्रतीक है।

भारतीय ध्वज का ऐतिहासिक विकास:

- वर्ष 1906: कोलकाता में पहला तिरंगा फहराया गया - लाल, पीला, हरा।
- वर्ष 1907: भीकाजी कामा ने पेरिस में झंडा फहराया - 'वंदे मातरम्', सूर्य-चंद्र प्रतीक।
- वर्ष 1917: एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक द्वारा नया झंडा प्रस्तावित।
- वर्ष 1921: पिंगली वेंकैया ने गांधीजी के सुझाव पर चरखे वाला झंडा बनाया।
- वर्ष 1931: कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को चरखे के साथ औपचारिक रूप से अपनाया।
- वर्ष 22 जुलाई, 1947: संविधान सभा ने इसी झंडे को मंजूर किया, लेकिन चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया।

संविधान सभा में ध्वज प्रस्ताव:

- पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत के ध्वज पर प्रस्ताव रखा।
- यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
- उन्होंने कहा कि यह झंडा किसी धर्म विशेष का नहीं, बल्कि समूचे भारत का प्रतीक है।

ध्वज से जुड़े कानूनी प्रावधान:

- **राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:** झंडे का अपमान करने पर 3 वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- **भारतीय ध्वज संहिता, 2002:** 26 जनवरी 2002 से लागू , नागरिक अब किसी भी दिन झंडा फहरा सकते हैं।
- **वर्ष 2022 का संशोधन:** अब झंडा रात्रि में भी फहराया जा सकता है, यदि उचित प्रकाश हो।
- **वर्ष 2021 का संशोधन:** अब झंडा मशीन-निर्मित और पॉलिएस्टर से भी बनाया जा सकता है। पहले केवल खादी (हाथ से बुना कपड़ा) मान्य था।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत अपनी तरह के विशेष मोबाइल एप्लिकेशन 'मेरी पंचायत' को एक्शन लाइन कैटेगरी में प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



➔ मुख्य बिंदु :

- यह सम्मान WSIS पहल के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS+20 हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान प्रदान किया गया।
- **आयोजक :** ITU और स्विस परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई।
- **सह- आयोजक :** ITU, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD द्वारा।
- WSIS प्राइज 2025 चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

‘मेरी पंचायत’ ऐप :

- पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की एक परिवर्तनकारी डिजिटल गवर्नेंस पहल हैं, जो 80 करोड़ ग्रामीण निवासियों, अधिकारियों और पंचायती राज के हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- यह पंचायत गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ावा देता है।
- यह ऐप ई-ग्राम स्वराज, GPDP, मनरेगा और अन्य जैसे विभिन्न पोर्टलों को एकीकृत करता है, जिससे नागरिकों को ग्राम पंचायत के कार्यों और पहलों के बारे में आसानी से जानकारी मिलती है।
- यह ऐप ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP), परियोजना ट्रैकिंग, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, सामाजिक लेखा परीक्षा उपकरण, निधि उपयोग डेटा और जियो-टैग्ड और जियो-फ़ेन्सड सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण तक पहुँच भी प्रदान करता है।
- 12 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला यह ऐप अपने बहुभाषी इंटरफ़ेस के माध्यम से समावेशिता सुनिश्चित करता है।